to the Lt. Governor, Delhi on the 19th October, 1973; and

(b) if so, the gist of the demands and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS: (SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT) : (a) and (b) : The demands made by the Lawrence Road Welfare Federation concern several agencies like the DDA, the Delhi Transport Corporation, the Delhi Municipal Corporation and the Delhi Administration A statement containing a gist of the demands along with the action taken or contemplated is placed on the Table of the House. [Placed in library. *See* No Lt 6613/74].

इन्दौर से बम्बई तक माइक्रोवेव लाईन

*552. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) इन्दौर से बम्बई तक सीधी माईक्रोवेव (टेलीफोन) लाईन डालने का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा, और

(ख) अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

संचार मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) (क) इन्दौर-धूलिया-बम्बई मार्ग पर अधिष्ठापन-कार्य चल रहा है। आशा है कि वर्ष 1976-77 के दौरान यह प्रणाली चालू हो जाएगी।

(ख) इंदौर से बम्बई की माइक्रोवेव लिंक प्रणाली उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो दिल्ली को बम्बई से जयपुर, कोटा और धूलिया के रास्ते से जोड़ता है और जिसमें बीकानेर, अजमेर और जोधपुर का सम्पर्क जयपुर से तथा अहमदाबाद और भोपाल का इंदौर से है। पूरी योजना 15.89 करोड़ रुपये की लागत से चालू की जा रही है। सभी स्थानों पर जमीन खरीद ली गई है और वहां से सड़कों का निर्माण हो गया है। इमारत और टावर बनाने का सिविल इंजीनियरी काम हो रहा है। सभी स्थानों के लिये रेडियो रिले उपस्कर कनाडा से मंगाया जा रहा है। सहायक सामान, जैसे मल्टी-प्लेक्सिंग उपस्कर, पावर प्लांट, बैटरियां, टावर का सामान आदि स्वदेशी साधनों से प्राप्त किया जा रहा है।

बिहार के एक डाकखाने से बीमा किए हुए लिफाफों का गायब हो जाना।

*554. श्री हुक्म चन्द कछवाय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई है कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा भेजे गए लगभग 60,000 रुपये के 6 बीमा मुदा लिफाफे एक डाकखाने में गायब हो गये है, और

(ख) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) (क) जी हां।

(ख) इस मामले में पुलिस को रिपोर्ट कर दी गई है और पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने अभी तक सन्देह में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक कर्मचारी रेल डाक सेवा का भी है। बिहार पुलिस और डाक-तार विभाग आपस में सम्पर्क बनाए हुए है।

Delhi-Gwalior Direct Dialling

*555 SHRI MADHAVRAO SCINDIA. Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether during a recent visit to Gwalior, the Postmaster-General of Madhya Pradesh had assured the Madhya Pradesh Chambers of Commerce that the Telephone Trunk Dialling system between Delhi and Gwalior will be completed in 1974; and

(b) the time schedule of the schemes ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI K. BRAHMANANDA

REDDY): (a) No record is available to indicate whether the Postmaster-General, Madhya Pradesh Circle had given an assurance to the Madhya Pradesh Chamber of Commerce that Subscriber Trunk Dialling Service between Delhi and Gwalior would be completed in 1974.

(b) Gwalior exchange is planned to be connected to the Trunk Automatic Exchange at Agra after its commissioning in early 6th Plan period Through Agra Trunk Automatic Exchange, Gwalior subscribers will be able to dial into Delhi telephone system.

मारुति कन्सल्टेंसी सर्विसिज

*561. श्री जगन्नाथ राव जोशी :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या औद्योगिक विकास मंत्री 'मारुति कन्सल्टेंसी सर्विसिज' के सभाव्यता प्रतिवेदन के आधार पर लाइसेंस जारी करने के बारे में 28 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2565 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) नवम्बर, 1970 में मारुति टेकनीकल कन्सल्टेंसी के पंजीकरण से पूर्व उसके विशेषज्ञों के नाम और उनके अनुभव क्या थे, और

(ख) नवम्बर, 1970 से अब तक ऐसे लाइसेंसों की संख्या क्या है जिनके सभाव्यता अथवा परियोजना प्रतिवेदन मारुति कन्सल्टेंसी टेकनीकल ने तैयार नहीं किए हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) मारुति टेकनीकल सर्विस प्रा० लि० कम्पनियों के रजिस्ट्रार दिल्ली और हरियाणा के कार्यालय में पंजीकृत है तथा इस मंत्रालय की परामर्शदाती फर्म के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। मांगी गई जानकारी इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

(ख) औद्योगिक लाइसेंस आदि के आवेदन पत्रों के साथ परामर्शदाती फर्म द्वारा तैयार की गई संभाव्यता परियोजना रिपोर्ट भेजना आवश्यक नहीं है। अत: संभाव्यता/परियोजना रिपोर्ट के आधार पर जारी किए गये औद्योगिक लाइसेंसों के आंकड़े नहीं रखे जाते। फिर भी, ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जिसमें मैसर्स मारुति टेक्नीकल सर्विसेज द्वारा तैयार की गई सभाव्यता अथवा परियोजना रिपोर्ट के आधार पर आशय पत्र जारी किया गया है।

देसूरी तहसील हैडक्वार्टर में एक स्कूल के निर्माण में रुकावट बनने वाले एक टेलीफोन पोल का हटाया जाना

*563. श्री मूलचन्द डागा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देसूरी तहसील हैडक्वार्टर पर जो पाली जिले (राजस्थान) में है, लड़कियों की पाठशाला के भवन का निर्माण रुक गया है क्योंकि अनुरोध किए जाने के बावजूद डाक और तार विभाग ने अपना पोल (खम्भा) नहीं हटाया है, और

(ख) क्या इस बारे में गांव वालों ने एवं अन्य व्यक्तियों ने डाक तथा तार विभाग को प्रार्थना पत्र भी दिया था, और यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) लड़कियों के स्कूल के पास से डाक-तार विभाग का खम्भा हटाने का अनुरोध मंडल इंजीनियर से तारीख 11 फरवरी, 1974 को किया गया था।

(ख) देसूरी के सरपंच और गांव के एक अन्य व्यक्ति ने मंडल इंजीनियर को तारीख 11 फरवरी, को तार भेजा है। खम्भा हटाने के खर्च (सिर्फ फुटकर खर्च) की बतौर 181 रु० का डिमांड-नोट देसूरी के सरपंच के नाम तारीख 15 मार्च को भेजा गया था, जिसकी अदायगी 29 मार्च को हो गई है। खम्भा हटाने का काम तत्काल शुरू कर दिया गया है।

Loss to Engineering Industries in West Bengal and Orissa

*564. SHRI GAJADHAR MAJHI :

SHRI SAKTI KUMAR SARKAR:

Will the Minister of INDUSTRIAL